रस की बातें सुनकर के बुड्ढों में भी कुछ उत्साह और जोश पैदा होगा और हो सकता है उनका बुढ़ापा कुछ ज्यादा दिन के लिए हट जाय। तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री इस मांग के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें कि वहां रेडियो स्टेशन होना नितान्त आवश्यक है। रेडियो स्टेशन की मेरी ही मांग नहीं, बहुत से लोक सभा के सदस्यों की मांग है, बहुत सी संस्थाओं की मांग है, जनता की मांग है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि देश की मांग है। इसलिये देश की इस मांग और जनता की मांग को वह विशेष रूप से ध्यान में रखें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन अनुदानों की मांगों का जवाब देंगे तो घोषणा करेंगे कि वहां ब्रज क्षेत्र में या ब्रज क्षेत्र के मुख्य स्थान मथुरा में जहां की मांग तमाम देश से पहुंची है, वहां पर रेडियो स्टेशन होगा।

दूसरी प्रार्थना मैं यह करना चाहता हूं कि जहां .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप और समय लेना चाहते हैं ?

श्री वि० सिं० चौधरी : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप सोमवार को जारी रखें।

15.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

EIGHTY-SECOND REPORT

Shri M L. Dwivedi (Hamirpur): Sir, I beg to move:

> "That this House agrees with the Eighty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 23rd March, 1966."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That this House agrees with the Eighty-second Report of the Committee on Private Member's Bills and Resolutions presented to the House on the 23rd March, 1966."

The motion was adopted

15.291-2 hrs.

RESOLUTION RE: FREE MOVEMENT OF FOODGRAINS IN THE COUNTRY—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Tan Singh on the 11th March, 1966:—

> "This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement and all zonal and other barriers to the free movement of foodgrains throughout the country be abolished immediately."

1 hour ond 20 minutes are left. Shri Bishwanath Roy may continue his speech.

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था उस वक्त मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता था कि सरकार द्वारा एकाधिकार वसूली की प्रथा ऐसी नहीं है जिससे किसी किसान को नुकसान या हानि हो। वह उनकी रक्षा के लिए भी है। उनकी आर्थिक रक्षा के लिए उसका उपयोग होता है। सम्भव है कि इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय के वहां अधिक अन्न होता हो और उनके वहां के किसानों को शायद अन्न बेचने का ही अवसर आता हो। लेकिन देश के अन्य भागों में ऐसा अवसर भी आता है जहां

[श्री विश्वदाय राय]

पर कि उत्पादन् बढ़ने पर भाव गिरते हैं और तब सरकार को उचित मूल्य किसानों को सुलभ करने के लिए भाव निर्धारित करके स्वयं उनसे अन्न खरीदना पड़ता है। एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ है। पिछली बातों को दुहराने के बदले मैं अपने उत्तरप्रदेश की अब की बात कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और तर्कसंगत रहेगा। इस वर्ष आलू का उत्पादन् उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक हुआ है। इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रोजगारियों ने, व्यवसाइयों ने भाव बिलकुल गिराये इससे बीच में सरकार को आना पड़ा। सरकार सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य पर आलू खरीद कर मद्रास और दूसरे प्रदेशों को भेज रही है। जाहिर है कि अगर इस तरह बीच में सरकार दखल नहीं देती और यदि यह प्रथा नहीं रहती तो किसानों पर, आलू उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता। अगर वह अधिपत्य व्यवसायी वर्ग के पास होता, जो आलू का जो रोजगार करते हैं उस व्यापारी वर्ग के हाथ में अगर इसका अधिपत्य होता तो साधारण किसानों को आलू उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती। आज देश में जो अन्न संकट विद्यमान है उसमें खाद्यान्न का उत्पादन जैसे भी हो सके तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। उस खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए किसानों को जो जी तोड़ कर परिश्रम करना है उस में एक बड़ा धक्का लगता क्योंकि जाहिर है कि खाद्यान्न का उत्पादन् तभी किसान बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे जब कि उन्हें प्रोत्साहन मिले और उनकी उपज का उन्हें उचित मूल्य मिले। आज जौन स्टुर्ट का समय नहीं है जो लंदन के उन्नीसवीं शताब्दी के एक एकोनामिस्ट हुए हैं और जिनका कि यह विचार था कि केवल उत्पादन् और मांग के आधार पर समाज की व्यवस्था चलती है। लेकिन आज वह चीज नहीं चलती है।

15.32 hrs.

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

यही नहीं कि वह हमारे जैसे समाजवादी देश में न चलती हो बल्कि अमरीका या जो अन्य जो पूंजीवादी देश कहे जाते हैं या जहां बिलकुल आर्थिक स्वतंत्रता है वहां देखा जाय तो उधर भी किसी न किसी रूप में वहां की सरकार को और वहां के राज्य को कुछ अधिकार रहता है, एकाधिकार भी कुछ रहता है वहां की आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। आज अपने देश भारत में तो आर्थिक व्यवस्था प्लांड है—नियोजित है। हम लोग इस बात के लिए बचनबद्ध हैं कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना करनी है। हर पांचवें वर्ष देश के हर बालिग को वोट देने का अवसर मिलता है और एक सच्चे प्रजातंत्री रूप में देश का शासन कार्य चलता जाता है। देश के एक छोटे से छोटे गांव के साधारण किसान से लेकर बड़े से बड़े करोड़पति और अरबपति देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य चलाया जाता है। निरंतर सरकार द्वारा हमारी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है ताकि कुछ दिनों के बाद यहां पर समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। एक ऐसा विचार लेकर चलना कि सरकार को एकाधिकार न हो और बिलकुल वह समाप्त कर दिया जाय एक ऐसी बात है जैसे यह बात है कि अपनी नींव तो एक सुदृढ़ तरीके से न बनायें और उसके ऊपर बड़ी इमारत ऐसी बनायें जो गिर जाय। जाहिर है कि ऐसा वही कर सकता है जिसके

विचारों में स्पष्टता न हो। देश की सामाजिक व्यवस्था के साथ आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में भी दिमाग में स्पष्टता न होने के कारण कोई ऐसी बात कर सकता है। जब एक बार संसद् ने आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य को मान लिया तो वह सारे राष्ट्र का लक्ष्य हो जाता है वह एक किसी वर्ग विशेष या किसी दल विशेष का ही लक्ष्य नहीं रहता है। ऐसी दशा में जब भारत का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित हो चुका है तब बिलकुल सरकार के एकाधिकार को समाप्त करना और कुछ व्यवसाइयों के अधिकार को स्थापित करना आज बीसवीं शताब्दी में उचित नहीं लगता है। आज इस तरह का प्रस्ताव आये यह मेरी समझ में यह बात नहीं आती है।

दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहूंगा वह तो आखिर सिद्धान्त की बात है या बड़ी योजना की बात है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी हम को बाहर से माल लेना ही पड़ता है। हो सकता है कैनाडा और अमरीका जैसे एक आध देश में जहां उपज काफी होती है और आदमी कम है वहां पर अन्न का बाहुल्य हो वहां पर उनकी आवश्यकता से अधिक पैदा होता ही हो लेकिन ऐशिया के देशों में और भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में बाहर से अनाज मंगाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी हालत में यह कहां तक उचित होगा कि हम सरकार के अधिपत्य को तो समाप्त कर दें और कुछ व्यवसाइयों के अधिकार को स्थापित होने का अवसर दें? उस हालत में विदेशों से जो भी हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसको हम किस आधार पर स्थापित कर सकेंगे? कुछ व्यक्तियों के हाथ में इस सारी व्यवस्था को देना और जिस रूप में यह प्रस्ताव लाया गया है उसे अगर मान लिया जाय तो जिस आर्थिक व्यवस्था और समाजवादी समाज बनाने को हम कृतसंकल्प हैं उस पर एक आघात पहुंचेगा।

अब यह हो सकता है कि राजस्थान के किसी भाग में जिसकी चर्चा प्रस्तावक महोदय ने की थी अन्न का बाहुल्य हो लेकिन देश के अनेक भागों में अन्न की कमी है और इस वर्ष तो खाद्यान्न की स्थिति और भी विषम है। इसके कारण देश में जो असन्तोष व्याप्त हो रहा है उसे यह विरोधी दल वाले और उभारने की कोशिश करते हैं और उसके परिणामस्वरूप जो जो दुखद कांड हुए हैं वह सभी के सामने हैं। अब जाहिर है कि कमी वाले क्षेत्रों में अन्न पहुंचाने के लिए अगर विदेशों से हमें अन्न पूरे तरीके से नहीं मिलता है तो कैसे काम चलेगा? चाहे वह राजस्थान हो चाहे पंजाब हो जहां भी अन्न उस क्षेत्र की आवश्यकता से अधिक है तो वहां का अन्न सरकार लेकर उन भागों में पहुंचायेगी जहां पर उसकी कमी व आवश्यकता है।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा): ब्लैक से बेचती है सरकार।

श्री विश्वनाथ राय : ब्लैक से बेचने की जो बात है तो वह माननीय सदस्य ज्यादा जानते होंगे। मैं तो उन क्षेत्रों से आता हूं जहां आमतौर पर अभाव रहता है और सदा ही बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है। यह बात नहीं है कि वहां के लोग काम नहीं करते हैं, वह काफी मेहनत मशक्कत करते हैं लेकिन आबादी इतनी घनी है कि एक वर्गमील में 1100 से कुछ अधिक व्यक्ति हैं। यह भी नहीं है कि वह कुछ पैदा नहीं करते। हमारे वहां के लोग चीनी बहुत अधिक पैदा करते हैं, वे खुद तो खाते ही हैं साथ ही औरों को और इनको भी खिलाते रहे हैं शताब्दियों से। लेकिन चूंकि आबादी वहां पर काफी घनी है इसलिए वहां अन्न का अभाव रहता

[श्री विश्वनाथ राय]

है और बाहर पर आश्रित रहना पड़ता है। वहां पर ब्लैक नहीं होता है बल्कि जहां सरकार पर कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा या राजकीय दुकानों द्वारा, कंट्रोल्ड शौप्स द्वारा विदेशों से मंगवाये हुए अन्न का वितरण कराती है। ब्लैक तो वहां पर होता है जहां उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं और हैडक्वार्टर पर ऐसे स्टाकिस्ट हैं जो थोक का व्यापार करते हैं और जो लोग उनके यहां रहते हैं ब्लैक वे लोग करते हैं। ब्लैक सरकारी दुकानों द्वारा नहीं किया जाता है जो जनता में गल्ला कंट्रोल्ड रेट पर देती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के एक हिस्से में जहां पर अन्न अधिक पैदा होता है और उसमें प्रस्तावक महोदय का वह भाग है जहां अधिक गल्ला उपलब्ध होता है वहां सरकार उस भाव से उन्हें कुछ कम देती है जिस पर वह वहां बेच सकते हैं। लेकिन सरकार यह भी तो करती है कि उस गल्ले को इस तरह से इकटठा करके दूसरी जगहों पर जहां अन्न उपलब्ध नहीं है वहां उचित मूल्य पर जनता को सुलभ करती है। अब यह कहें कि सरकार उन्हें कुछ कम देती है और उससे ज्यादा उन्हें व्यवसायी देते हैं तो वह यह क्यों भूल जाते हैं कि देश के उन भागों में जहां अन्न की कमी है वहां की जनता को सरकार उचित मूल्य में अनाज सुलभ करती है जबकि व्यवसाइयों के हाथों द्वारा ऐसा होना सम्भव नहीं है। यह जो सरकार द्वारा एकाधिकार है यह सारे देश और समाज की आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए किया जाता है।

प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में प्रस्तावक महोदय ने जोनल और दूसरी बैरियस हटाने की मांग की है। अब सरकार उस पर विचार कर रही है और हो सकता है कि वह किसी हद तक हट भी जाय। सरकार को नियंत्रण और जोन आदि की व्यवस्था समूचे देश के हित को ध्यान रख कर करनी पड़ती है। अब चीनी का ही मामला ले लीजिये। मैं इस पर इस समय अधिक नहीं कह सकता लेकिन जब चीनी का उत्पादन कम था तब नियंत्रण और कंट्रोल रखना था ही। अब चूंकि चीनी का उत्पादन बढ़ गया है इसलिए हो सकता है कि सरकार उस के बारे में नई नीति बनाये। यहां पर समय नहीं है कि मैं अधिक उस पर कहूं लेकिन जोंस हटाने की बात भी सरकार ने एक तरीके से मानी है और उस पर वह विचार कर रही है। उस के सम्बन्ध में संशोधन करने की बात हो रही है। अनेक बार इस पर चर्चा हो चुकी है। इसलिए फिर जब अवसर मिलेगा तब मैं कहूंगा कि चीनी पर से कंट्रोल बिल्कुल खत्म किया जाय या न किया जाय। किसी न किसी तरीके की इस में ढील करने की बात कांग्रेस दल के लोगों ने भी मानी है लेकिन यह कि बिलकुल किसी तरीके का नियंत्रण न हो इस बात को स्वीकार करना मैं समझता हूं वह एक ऐसा क़दम होगा जो आगे चल कर देश को हानि पहुंचा सकता है। जिन के हित की बात प्रस्तावक महोदय कर रहे हैं उन्हीं को नुकसान हो सकता है। अब यह बात दूसरी है कि जोंस का रूप आगे क्या हो, बड़ी बड़ी जोंस हो जायें लेकिन सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने का जो प्रस्ताव है यह देश के लिए समाज के लिए और गरीब किसानों के लिए, उन 80 प्रतिशत ग्रामीण किसानों के लिए जो गांवों के रहने वाले हैं उन के लिए बड़ा अहितकर होगा और वह उन के लिए हितकर नहीं होगा इसलिए मैं इस मौजूदा प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): Mr. Chairman, Sir, this Resolution, which has been moved by my hon. friend, Shri Tan Singh, has got two basic aspects. One is the zonal restrictions which have been put on wheat, rice and other grains in the country and the second aspect is that of leaving the entire trade in foodgrains absolutely free, whether to be done by Government or to be done by priavte individuals. First I would like to say a few words regarding zonal restrictions. It is true that ours is such a big country that there are bound to be different kinds of conditions prevailing at the same time in the country. In certain areas there will be surplus foodgrains and in certain areas there will be deficit. Now, it would be advantageous in one set of circumstances and conditions to have restrictions on the movement of the foodgrains, while it will not be advantageous for having these restrictions on different set of circumstances and conditions.

Now, Sir, at the moment, as we have seen, I would like to draw the hon. Minister's attention to a particular and specific example which is today prevailing in the Punjab markets. There is enough of surplus gram and wheat. The result is....

An hon. Member: Maize also.

Shri Inder J. Malhotra: Maize also. The result is, the prices have been fluctuating to such a length that ultimately the farmer has started feeling, or, rather having a very strong feeling, whether it is proper and advantageous for him to grow wheat in the coming season.

It is the responsibility of the Government to provide foodgrains to the consumers. It is also the responsibility of the Government to see that whatever little incentives you have already given to the farmers are properly guarded and safeguarded, so that it should not have adverse effect on the agricultural production of our country.

Sir, I have been able to discuss this matter with the Punjab ministers also; and I also pleaded before them that it is the first responsibility of the Punjab Government to enter the market immediately and buy whatever surplus gram, maize or wheat is existing in the country which is having adverse effect on the market prices. But they were rather reluctant to do this on the Government level. I would therefore suggest to the Central Government that the Central Government should see that such conditions should not be allowed to prevail. and if such conditions have come to exist, they must take immediate steps to see that the condition does not further deteriorate.

Regarding the removal of zonal restrictions I would start from wheat and coarse grains and then go to rice. Now, there has been a rather agreed and unanimous demand all over the country that zonal restrictions should be removed. Now there are arguments which can be for or against this; and it will not be possible for me to go into the arguments. I would only say this, that this year and in the coming year our condition regarding wheat is going to be—if not much better—at least a little better than it was last year. Now, I ask: Why can not Government take a bold decision and start with the wheat and the coarse grains and remove all the zonal restrictions which are now existing in the movement of these foodgrains in the country? With this serving as a sort of basis, basis of the experiment, then our bigger or major difficulty always is in regard to rice. Then, after the experiment we gain regarding wheat and coarse grains as a result of the change in the zonal restrictions, we can later on also think about either removal or continuance of the policy which we are now adopting as far as the restrictions on rice are also concerned.

In this connection I would say, Sir, that apart from the very large section of the congress party feeling about the zonal restrictions, organisations

[Shri Inder J. Malhotra]

like the Farmers' Parliamentary Forum where certain hon. Members of this House are also there, have, after thorough examination, also come to the decision that the zonal restrictions on wheat and course grains should be removed immediately.

Sir, regarding the idea of leaving the trade of the foodgrains absolutely free in our country, I would not like to agree with the Mover of the Resolution, for the simple reason that India is a perpetually deficit country in the production of foodgrains; and I do not share even for a single minute, the assurances, repeated assurances, given by the hon. Minister that India is going to be self-sufficient after five years. I do not agree with that at all even for a single minute. We are going to face this problem. We will face this problem as long as we do not do something drastic to check the rate of growth of our population, and, at the same time, giving more incentives for increasing agricultural production in this country.

Now, Sir, since we are going to be always deficit in foodgrains, our Government, a Government which has been put into power by the people of this country, could not allow the private individuals and the private traders to play havoc with a commodity like foodgrains in this country.

Sir, why is it not possible to leave the foodgrains trade absolutely to the private individual? We have seen that with the little manipulation of introducing more finances in the market or withdrawing the loan finances from the market they can play havoc with the market prices of foodgrains in this country, for which ultimately the consumers are going to suffer. Producer is going to suffer and there is going to be absolute chaos as far as the trade regarding the foodgrains is concerned.

Sir, I would also at this time appeal to the Government that while the Government feels its responsibility to import foodgrains from other countries, Government should also be more responsible and more anxious to see that whatever grain is produced in this country is properly procured, properly stored, and in respect of whatever deficit is left, we should try to see that every year that deficit is reduced and it should never be allowed to be increased.

Now, Sir, in the past also I had been pleading rather strongly that to put the trade of the foodgrains on the right lines, it is very necessary for the Government to have once for all, some final decision. Let us not do it in a half-hearted way. If the Government feels that it is proper for the Government to have monopoly procurement programme, they should have monopoly procurement programme being implemented in every State by the State Governments. If the Government does not feel that the time has come when there should be monopoly procurement programme, then, let it be voluntary procurement being organised by the cooperatives, State Governments and other organisations.

With these words, Sir, I support part of this Resolution as far as the removal of the zonal restriction is concerned, but I should express myself strongly, that I am not willing to agree with my hon. friend that the trade of foodgrains should be left absolutely free to the private individual.

Shri Ranga (Chittoor): He does not say so.

Mr. Chairman: I would like to know from the hon. Minister how much time he would like to take for intervention.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) इसके लिए कुछ समय बढ़ा दिया जाये ।

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): Fifteen to twenty minutes.

Mr. Chairman: Mr. Tan Singh, how much time will you take for reply?

Shri Tan Singh (Barmer): Fifteen minutes.

Mr. Chairman: Fifteen plus fifteen minutes—that is, half-an-hour. I have got a list which shows that there are ten Members remaining who are anxious to speak. So, I think, we should restrict ourselves to seven minutes each. It will be better. If any hon. Member wants a minute more, he may have it. I think it will be better if we have seven minutes each, ordinarily.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कुछ ऐसे भी मेम्बर हैं, जिन्हों ने नाम नहीं भेजे हैं ।

An hon. Member: Time may be extended.

Mr. Chairman: Ordinarily seven minutes, and maximum, one more minute. Shri Bade. Please restrict yourself to seven minutes.

श्री बड़े (खारगोन) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है : "इस सभा की राय है कि अनिवार्य एकाधिकार वसूली पद्धति और देश भर में खाद्यान्नों के निर्बाध रूप से लाने-ले जाने के मार्ग में समस्त क्षेत्रीय तथा अन्य प्रतिबन्धों को तत्काल समाप्त किया जाये ।" मैं इस प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

पहले मध्य प्रदेश को सरप्लस स्टेट कहा जाता था, लेकिन जोन बनने के बाद हमारे यहां से चना गुजरात को भेजा गया और जवार महाराष्ट्र को भेजी गई, जिस के कारण हमारे यहां बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई । मैं ने देखा है कि महाराष्ट्र में जोन्ज की वजह से लोगों को अनाज नहीं मिलता है और वहां भुखमरी हो रही है ।

पहले जोन बनाए गए । उस के बाद जिलेबन्दी की गई । उस के बाद तहसील-बन्दी की गई और फिर टप्पाबन्दी की गई । इस वजह से अनाज एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता है । मध्य प्रदेश में गुना में गेहूं पड़ा हुआ है, लेकिन वह बैस्ट निमाड़, खारगोन डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता है । एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मूवमेंट बन्द करने से यह स्थिति पैदा हो गई है कि एक जगह के लोग भूखों मरते हैं और दूसरी जगह गेहूं सड़ रहा है । पंजाब में गेंहूं सस्ता मिलता है और वे चाहते हैं कि इसको बाहर लेजाकर बेंचे, खाने के वास्ते दें, लेकिन सरकार तैयार नहीं है । केवल फूड मिनिस्टर साहब अड़े बैठे हैं और कहते हैं कि पंजाब के काश्तकार और वहां के व्यापारी ब्लैक-मार्केट कर के फायदा उठाना चाहते हैं । इस वास्ते उनको इजाजत नहीं देते हैं । हमारे खाद्य मंत्री भी अपना रास्ता देख रहे हैं कि कब ये हमारी शरण आयें और जिस भाव में सरकार उस अनाज को वसूल करना चाहती है, उस भाव में वसूल कर सकें । इस का एक और परिणाम सामने आया है कि व्यापारी अनाज को चोरी से एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं । 500 रु० देते हैं बार्डर पर और एक ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है, बार्डर पर पुलिस बैठी रहती है लेकिन अनाज चला जाता है, इस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग और भ्रष्टाचार शुरू हो गया है । जितने जितने कानून सरकार बनाती है, उससे भ्रष्टाचार का मार्ग खुल जाता है ।

इस के साथ एक और दोष भी सामने आया है जितने हमारे यहां छोटे छोटे व्यापारी

[श्री बड़े]

थे जो अपना माल लाकर बाजार में बेचते थे, वह बन्द हो गया है । 20 लाख ऐसे छोटे छोटे व्यापारी थे जो इस तरह से अपना धन्धा करते थे, वह आज बन्द हो गया है, लेकिन जहां काश्तकार अपना अनाज व्यापारी को अपनी झोपड़ी में ही बेच दिया करता था, आज उसको 10-20 किलो या फिर आधा क्वीन्टल अनाज लाकर तहसील स्थानों में जाकर बेचना पड़ता है और फिर पैसा लेने के लिये उसको तीन चार चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर आधा क्वीटल जो लेवी से प्रोक्योरमेन्ट होता है उसका पैसा लेने के लिये उसको कई दफा जाना पड़ता है । शासन यह चाहता है कि एकाधिकार कर के सब व्यापारी अपने हाथ में लेकर लोगों को भूखा मारे इस से बुरी सरकार दूसरी कोई नहीं हो सकती । गांव गांव में शहर शहर में लोग इस सरकार को कोस रहे हैं कि यह किस प्रकार का कांग्रेस शासन है जो लोगों को भूखा मार रहा है ।

उत्तर प्रदेश में भुखमरी से मौतें नहीं हुई हैं, ऐसा वहां के राजस्व मंत्री ने कहा है । जब हमारे मध्य प्रदेश की विधान सभा में यह सवाल आया कि भुखमरी से मर गये हैं तो कहते हैं कि भूखमरी कोई डिजीज नहीं है । मैं मानता हूं कि यह कोई डिजीज नहीं है लेकिन उससे रिकेट्स होता है, गश आता है, और कई बीमारियां पैदा होती हैं, हो जाती हैं लेकिन यह ठीक है कि एलोपैथी में भुखमरी कोई बीमारी लिखी हुई नहीं है । इस लिये विधान सभाओं में लिख देते हैं कि भूखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई, लेकिन ये मत्यु भुखमरी से नहीं हुई तो किस चीज से हुई, अनाज खाने को नहीं मिला तो उससे बीमारी हो गई और वह इस सरकार की गलत नीति के कारण हुआ ।

राजस्थान विधान सभा में भी इसी प्रकार का उत्तर दिया गया कि टोंक में भूखा होने से मृत्यु नहीं हुई । यह सब कांग्रेस शासन की गलत नीति का परिणाम है क्योंकि खाद्य मंत्री अपनी नीति पर अड़े बैठे हैं । वह कहते हैं कि हम जोन सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे, तहसील बन्दी नहीं तोड़ेंगे । बड़े कलैक्टर अपने अपने क्षेत्र में मुगल बादशाह हो गये हैं, जो उनके मन में आये वैसा करते हैं और सरपंच अगर वहां जाते हैं तो पर्दे के अन्दर कलेक्टर साहब बैठते हैं और कहते हैं कि अनाज नहीं है । अगर वह मिलने के लिये कहते हैं तो कह देते हैं कि फुरसत नहीं है और चपरासी उनको वहां से निकाल देते हैं आज जनता कहती है कि ये सब लोग पैसा खाते हैं, तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिये । हमारे यहां एक आदर्श है, श्री राम ने, जब सीता के बारे में लाछन लगा दिया गया, तो उन्होंने सीता का त्याग कर दिया । मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी का त्याग करें, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि अपनी कर्सी छोड़ कर गांव में चल और अपनी पत्नी को या एम० पी० की पत्नी को वहां खड़ा किया जाय क्यू में अनाज लेने के लिये, तब आपको सही परिस्थिति का ज्ञान होगा । जो गरीबों का अन्न है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा यह तो उनको मिलना ही चाहिये ।

स्वर्गीय श्री किदवई साहब ने क्या किया था ? उन्होंने एकदम कन्ट्रोल को छोड़ दिया था, हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उस वक्त उन को बहुत अच्छा पीरियड मिल गया था, इस वास्ते वह सक्सेसफुल रहे । लेकिन मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप कन्ट्रोल छोड़ दें तो अनाज ही अनाज हो जायगा और आज जो 20 लाख छोटे छोटे व्यापारी बेकार हो गये हैं, जो अनएम्प्लायमेन्ट उन के अन्दर बढ़ती जा रही है, वह दूर हो जायगी और यह जो भुखमरी आज हो रही है, वह दूर हो जायगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

Mr. Chairman: Mr. Rane.

Shri M. R. Krishna (Paddapalli): I am also standing.

Mr. Chairman: But the hon. member has not given his name.

Shri M. R. Krishna: I thought I would catch your eye.

Mr. Chairman: It is possible both ways. (*Interruptions*) Mr. Rane.

Shri Rane (Buldana): I stand to support the abolition of food zones immediately. The Food & Agriculture Minister has appointed an expert committee to go into this question and the Government is awaiting that report. But from the trend of thoughts of the Government during the last month, I am afraid the expert committee will give an opinion that the zones should continue in the interest of the country. This is my apprehension and this is based upon the trend of thoughts of Government during last month.

I wrote a letter to the Food Minister on the 8th July, 1964 and I pleaded with him that, without the abolition of the zones, the question of food shortage cannot be solved. The zonal system was introduced in 1964, either in April or May, and that was, with a particular purpose. Many members might be remembering this that in this House, there was a cry that the prices were soaring high. In order to arrest the rise in prices, the food zones were created, but they have not arrested the prices. My submission is that the shortage of food was created by this zonal system. There is a proverb that a remedy should not be more dangerous or detrimental than the disease. This zonal system has proved to be a remedy which is more dangerous and it has created all sorts of difficulties about the food situation. What is the position today?

In one State, a consumer can get wheat at the rate of Rs. 50 per quintal, bajra at about Rs. 42 per quintal and maize at about Rs. 39 or 40 per quintal. If you go to Maharashtra, a deficit State, you will find that a consumer gets wheat at the rate of Rs. 150|- per quintal and bajra and maize also for more than Rs. 100|- per quintal. Is it equality? Was it meant to create such an inequality in prices or even in distribution? I wrote a letter to the Prime Minister last year and to the Food Minister in 1964 that, in Maharashtra, a person gets two or three kilos per month; that means, about ten tolas per day, while in some other States, a man gets ten kilos per month per head. This disparity in distribution, disparity in prices, and all these problems are created by the zonal system. So I plead with the Minister that the zones should be immediately abolished. The Maharashtra Government is pleading this from the very beginning and the Maharashtra Pradesh Congress Committee has pleaded all along that the zones should be abolished. Some few days back, the Praja Socialist Party in Maharashtra has demanded reorientation of the food policy and their demand is that the zones should be immediately abolished. My submission is that this is a psycho'ogical moment to consider this issue of abolition of food zones. The Government can at least consider the question of abolition of wheat zones or jowar zones or bajra zones. If the Minister is very keen and intent on keeping the rice zones, we do not mind, because the majority of States are not rice-eating areas. Rice is a staple food in Andhra, in Madras, in Kerala, in Bengal and in Orissa. But the rest of the country can eat wheat, maize, bajra, jowar or some other coarse grains. When we are now getting 10 millions tons of wheat from America, this is the most psychological moment for abolishing at least the wheat zones. This is my submission.

16 hrs.

I want to place before the Minister that we must take a lesson from the past. When Shri Munshi was our Food Minister, when we were faced with this question, I shall read out a few lines from what he stated in February, 1952 in the provisional Parliament.

[Shri Rane]

"I must frankly tell you . . .

He told the members of the provisional Parliament

"....that a part of our difficulty is created by inter-State bans. In surplus States there is a natural tendency to utilise internal productions for their own people at low price by easy procurement or restricted export. The marketable surplus remains unprocured and therefore unavilable for exports. If the inter-State zones are removed, all the marketable surplus would be available."

My submission is that this happened in 1952 when the ration and the zonal system were there. Mr. Munshi was faced with the same question with which now our present Food Misister is faced. In 1957 when Mr. A. P. Jain was the Food Minister he also introduce it. But he also failed in his attempt. The zonal system has failed continuously and I submit that the zonal system should be immediately abolished

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : सभापति महोदय, जोनल सिस्टम को हटाने के लिये इस हाउस ने बार बार रिक्वेस्ट किया है और फूड मिनिस्टर साहब को धन्यवाद है कि उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वह इस बात पर विचार करेंगे । मेरा निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द विचार होना चाहिये । अगर चावल की कमी है तो कम से कम जो कोर्स ग्रेन्स हैं, जैसे चना, मक्का और इस तरह की दूसरी चीजें हैं, उन के सम्बन्ध में जोनल सिस्टम जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिये क्योंकि यह गरीबों के खाने हैं, और गरीबों की तादाद 85 फी सदी है । जोनल सिस्टम की वजह से इन के भाव जहां यह चीजें पैदा नहीं होतीं, बहुत ज्यादा हो गये हैं और जहां पैदा होती हैं वहां यह भाव गिर रहे हैं ।

दूसरा सुझाव मुझे यह देना है कि हमारी गवर्नमेंट की पालिसी मिक्स्ड एकानमी की है लेकिन गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई ऐसी मशीनरी नहीं बन पाई है जो गांव गांव में दुकानें खोल सके और लोगों को इन चीजों को, इन खाने की चीजों को मुहैया कर सके । इसलिए जब तक इस का प्रबन्ध नहीं हो जाता, यह जरूरी है कि मिक्स्ड एकानमी के अन्दर गवर्नमेंट ने जो फूड ग्रेन कारपोरेशन बनाया है वह भी जिस तरह से अन्य व्यापारी बाजार में जा कर चीजें खाने की खरीदते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से खरीदें । इस से फायदा यह होगा कि कम्पिटीटिव मार्केट होने की वजह से ऐग्रिकल्चरिस्ट को अच्छी प्राइस मिल जायगी और सरकार को बफर स्टाक मिल जायेगा । इसलिये जिन प्रान्तों में अभी तक फूड कारपोरेशन नहीं बनाया गया है वहां पर उसे बन जाना चाहिये ।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि चूंकि अक्सर यह कहा जाता है कि ब्लैक मार्केटिंग होती है जिस की वजह से होर्डिंग होती है, इसलिये होर्डिंग के ऊपर जितनी निगरानी और कड़ाई की जा सकती है की जाये, लेकिन फूड ग्रेन का मूवमेंट जो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को होता था उस को बन्द न किया जाये । इस से देश की इंटग्रिटी खत्म हो जाती है । देश के लोग समझते हैं कि वह एक देश के बाशिन्दे नहीं हैं, बल्कि वह बंगाल के बाशिन्दे हैं, बिहार के बाशिन्दे हैं । इस तरह से सारे लोग अन्य अन्य प्रान्तों में बटे हुए हैं । नैशनल इंटेग्रेशन के ख्याल से इस को जल्द से जल्द खत्म किया जाये ।

यह सरकार 18 वर्षों से है । सपोर्ट प्राइस पहली बार धान, गेहूं का किया, लेकिन गवर्नमेंट ने अन्य किसी खाद्यान्न की नहीं तय की । मैक्सिमम प्राइस फूड ग्रेन्स की नहीं होनी चाहिये, उस की मिनिमम प्राइस रक्खी जानी चाहिये और वह सपोर्ट प्राइस

होनी चाहिये । हमारे फूड मिनिस्टर ने इस के लिये जो कदम उठाया है उस के लिये उन को धन्यवाद है । अब तक किसी भी फूड मिनिस्टर ने ऐसा नही किया जैसा सुब्रहयम साहब ने किया । लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे ग्रेन्स हैं जैसे मेज है, ग्राम है या दूसरी चीजें हैं, सिवा व्हीट राइस के जिन सीरियलस की कीमत गवर्नमेंट ने तय नहीं की है । गवर्नमेंट अभी तक इस के बारे में एन्क्वायरी कर रही है । मेरा निवेदन यह कि यह एन्क्वायरी जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिये और इस मामले में कास्ट आफ प्रडेक्शन ठीक हो जाना चाहिये और सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलनी चाहिये ।

जहां तक गवर्नमेंट की मोनोपोली का सवाल है, लोगों ने कहा कि कोआपरेटिव के जरिये और दूसरे जरियों से इस का इन्तजाम होना चाहिये । यह चीज पब्लिक सैक्टर में आनी चाहिये, प्राइवेट सैक्टर में नहीं रहनी चाहिये । मेरा अपना अनुभव यह है, और हाउस में भी यह बात आई है कि हो सकता है कि कहीं की कोआपरेटिव अच्छी हों, लेकिन जनरली हम लोगों का, जो कि देहात में रहते हैं, इम्प्रेशन यह है कि जितनी वंगलिंग प्राइवेट सैक्टर वाले करते है उस से कम वंगलिंग पब्लिक सैक्टर वाले नहीं करते हैं । इस लिये सारी चीजों की दवा कोआपरेटिव ही है, इस में मैं विश्वास नहीं करता ।

मेरा निवेदन तो यह है कि सरकार को इस बात से डरना नहीं चाहिये कि जोनल सिस्टम हट जाये, कंट्रोल हट जाये तो चीजों के भाव बढ़ जायेंगे । बार बार यह बात दोहराई गई है, लेकिन यह ठीक नहीं है । गांधी जी ने कहा था कि कंट्रोल से तरह तरह की बुराइयां समाज में आ जाती हैं इस लिये उस को हटा देना चाहिये । किदवई साहब ने हिम्मत कर के अपने वक्त में उसे हटा दिया उस से भाव बढ़े, लेकिन वह भाव ज्यादा दिन तक नहीं रह सके क्योंकि कम्पिटीशन में भाव उठते और गिरते रहते हैं । फूड ग्रेन ऐसी चीज नहीं है कि जिन को दो चार, पांच या सात साल तक रख लिया जाय । वह साल भर में खराब हो जाते हैं, इस लिये कोई भी व्यापारी साल या छः महीने से ज्यादा उसे अपने पास नहीं रख सकता । इस लिये इस भय को दिमाग से निकाल देना चाहिये और जितनी जल्दी हो सकें इस पर फैसला कर के कारंवाई करनी चाहिये ।

Shri Ranga: Mr. Chairman, I am very glad that some very strong sentiments and expressions of opinion have come from some of our Members on the other side, Mr. Rane, Mr. Malhotra and now Mr. Tiwari. Sir, let there be no misunderstanding in regard to this Resolution. This Resolution is not opposed to mixed economy. We are also as much for it. The difference between the Government's side and ours is that we believe in mixed economy but they put too much stress on it; we put too much stress on the freedom side. That is the only main difference.

The second thing is we stand for the fixation of minimum price for all foodgrains including coarse grains and for pulses, gram and so on. We want the Government to play its effective role there. From what has fallen from the lips of my friend, Mr. Malhotra and Mr. Tiwari, it is clear that the Government has not been playing its role as effectively as it should in regard to fixation of minimum price at a reasonable level and maintenance of it. That is one of our charges. But that is not germane to this particular resolution. When we say that there should not be monopoly procurement, we only want that mixed economy should have its operation and that Government should also procure foodgrains through the Food Corporation, and help the Food Corporation to have sufficient funds from Government, from the Reserve Bank, from the State Bank and the commercial banks also so that it would be able to extend its operations over the whole

[Shri Ranga]

of India in respect of all the foodgrains and also pulses and make as many purchases as possible, and in that way it would be possible for them to prevent the merchants from playing mischief with the peasants. We know that the merchants are just as much capable of exploiting the peasants and playing mischief with them as the Government would do if they alone were to have the monopoly. Therefore, we do not want either the Government or the Food Corporation on the one side or the merchants on the other side to be the only purchasers or the only customers so far as the peasants are concerned. The peasant must have the freedom to make a choice between the Food Corporation on the one side and the ordinary merchants on the other. Let them compete with each other so that the farmers would have the necessary incentive and they would be able to have proper prices for themselves. But even then, there would be a danger of the prices going down too low as it happened in Gujarat and also Rajasthan because of over-production in certain areas. That is why we want that the minimum also should be maintained.

I am very glad to find that there is a general consensus on the side of the Congress also in favour of the removal of these zones. My hon. friend opposite who hails from Kerala ought to be able to know more fully than many others the rigours and the awful consequences of the zonal system that we have had. There is the need for appointing a committee now There was a time when Shri Jawaharlal Nehru was alive, when I was also one of his colleagues in some of the highest committees, when I was asked to take up some responsibility. I said that I should have the freedom to remove those controls which were there at that time, but he was not willing. That was one of the reasons why I left the Congress then. Then, we went out and we defeated the Madras Government, the Congress Government that was there. And what was the result? We insisted upon Rajaji being the Prime Minister or the Chief Minister of that State the Congress Party itself did that, and he took courage in both his hands and removed controls with the help of Rafi Ahmed Kidwai, and Rafi Ahmed Kidwai sat by the side of Shri Jawaharlal Nehru and managed somehow or the other Shri Jawaharlal Nehru as well as the whole system in the country, and gave a boon of freedom for the people from those controls. Did the country go to dogs then? Was there starvation? And did the prices go sky-high as they are now going Were there the kinds of struggles that we have now had in Kerala and Bengal only the other day? No. On the other hand, the prices came down and yet they remained at a sufficiently remunerative level; the peasants did not suffer and the consumers did not suffer; the only people who suffered were the corrupt officials and all that huge administration tha they had built up in the name of the so-called controls.

Therefore, what we want now is not that there should be complete freedom for the traders; no, we do not want that, We do not want Government alone to be the agency having the monopoly procurement either thereby perpetuating the kind of exploitation that is going on on our peasants in all those areas where there is surplus production and also the exploitation of the consumers in other areas.

Secondly, we want freedom of movement. When we ask for this freedom of movement also, we are extremely anxious that these check-posts must be removed. If freedom of movement were to be brought in, I can assure Government that things would improve. Let them hand over charge in regard to this particular matter for three to six months to me, and I would be able to show them that there is a real solution, not merely from the Swatantra side but from the side of commonsense in this country, which is now expressing itself from the Cong-

ress Benches as well as from everywhere else. We would be able to assure our people of freedom from exploitation by the Government officials and the check-post officials and the police and such other people who are running this rig now on the one side and also the merchants on the other.

Shri Balakrishnan (Koilpatti): May I bring to the notice of the hon. Member that when Rajaji was the Chief Minister of Madras, there were starvation deaths in Madras?

Shri Ranga: I do not know for how long my hon. friend has been in politics. If he were to refer to the papers of those days, he would be able to see that that is not correct. I may tell him that what he has said is not correct and is not true. There were no starvation deaths. It is true that some allegations were there, but it was proved to the hilt that there were no starvation deaths. So, what is the use of my hon. friend's saying this kind of thing? Were there starvation deaths in other States whose Governments were also their own Governments? It was their own Government in power in all those States. Rajaji also was their leader at that time; only now he happens to be my leader. (*Interruptions*).

Shri Balakrishnan: I was also a Member at that time, and he was also a Member.

Shri Ranga: What we want is just this. We want complete freedom of movement for the foodgrains to move on the roads and also on the railways, for the Government as well as the Food Corporation on the one side and also the private traders on the other, and also consumer's co-operatives and panchayat samitis on the third side. But what is happening now is this. As my hon. friend Shri K. N. Tiwary has also said, consumers' co-operative societies are also not the proper solution. We have had the scandals in regard to them in Rajasthan, in Delhi, in Punjab and other places, and we are seeing now what the Congress Members of Legislatures have themselves been saying in Madhya Pradesh and Rajasthan etc. in regard to the BDOs.

Mr. Chairman: The hon. Members should try to conclude now.

Shri Ranga: I would conclude by saying that this is a resolution which ought to be treated as embodying the consensus of the public opinion that today prevails amongst most of the Congress people and most of us here who stand from the Swatantra Party, and also, as Shri Rane has said, even the PSP, the only difference that there might possibly be to some extent in some limited area might arise from some of our communist friends, but I hope that they would also see the writing on the wall that these zonal controls have brought all this misery, and that monopoly procurement and all that kind of thing to the extent that hey have been there have not yielded good results but bad results.

Therefore, it would be best for the Government to remain loyal, so far as this particular problem is concerned, to their own profession of mixed economy, and to have the courage to allow competition from free trade even while developing their own Food Corporation and its activities in respect of all the foodgrains and providing minimum price protection for all the foodgrain producers.

Shri Bade: They will remove the barriers when the elections will be there.

Shri Muthiah (Tirunelveli): Mr. Chairman: Shri Tan Singh's resolution says that compulsory procurement and zonal barriers should be abolished immediately and free movement of foodgrains throughout the country should be allowed. As an ideal this is all right, and neither the Government nor the people would object to this. I stand for the abolition

[Shri Muthiah]

of the zonal restrictions and for the free movement of foodgrains ultimately, that is, at the proper time and not immediately. The question is one of time . The question is whether compulsory procurement and zonal restrictions could be abolished immediately and free movement of foodgrains could be allowed throughout the country now. Does the present food situation warrant it? What are the consequences that would follow if such a step is taken? All this should be dispassionately considered by every hon. Member of this House. Such a step can be taken if food production in India is commensurate with th demand if imports have become unnecessary and if sufficient stocks are always available with Government and if the traders have become more responsible towards the common man and care for their welfare more than for their profits . But today these conditions do not exist. The country's production is quite inadequate to meet the demand. The food grains productions in 1965 was unusually low, because of the total failure of rains in many States and the worst drought experienced by them in recent history. The production in 1965-66 was 75.9 mililon tons whereas the production in 1964-65 was 88.4 million tons. The shortfall in 1965-66 is estimated to be about 14 to 15 mililon tons. There was a great shortfall in rice production also. There were near famine conditions in several States such as Gujarat, Rajasthan, and Maharashtra. Relief works were started in these States to provide work and bread to thousands and thousands of people. The country is far away from self-sufficiency in food production. The Third Plan target of 100 million tons has not been achieved. The population is growing fast at the rate of more than a crore a year. Government has a special responsibility to feed the people since our State is a socialist state, a welfare state, and since our objective is the establishment of a democratic and socialist society.

Imports were necessitated by food scarcity conditions in 1965-66 and 1966-67. In 1965-66, Rs. 290 crores worth of foodgrains were imported. We have received generous help from the USA which has authorised 6.5 million tons of wheat and coarse grains for 1965-66 under PL 480 and has promised substantial quantities for 1966-67. The rice imports in 1965-66 were of the order of 7.83 lakh tonnes. But for 1966-67, import of rice has become impossible since rice is not available in foreign countries.

All these imports mean a drain on our foreign exchange. But starvation of the poor people of the country has to be stopped at any cost by Government. No responsible government can shirk this responsibility. The traders in India, I submit, cannot fulfil this great responsibility. I feel that it is risky to entrust this to them in the particular conditions that obtain today. Traders gererally are not quite public spirited; they care for profits more than for the welfare of the poor people.

Mr. Chairman: He cannot say that of all traders.

Shri Muthiah: Most of them. Most of the traders have mainly the profit motive in mind. In conditions of extreme scarcity, they will hoard stocks and push up prices and profiteer very much at the expense of the common people. For example, traders in Punjab and Rajasthan are today holding back huge stocks of food grains brought from producers at control rates in order to sell them at exorbitant prices later. Traders in Punjab are holding back about 70,000 tons of wheat and 1,00,000 tons of gram. Hoarders in Rajasthan are holding back 60,000 tons of gram. Huge surplus stocks of rice and wheat in Andhra Pradesh, Orissa and Punjab and

coarse grains in Rajasthan are with traders now. Government are concerned at this and are making great efforts to buy these stocks and distribute them to the deficit States, to needy people. Government are trying to build up stocks by internal procurement. For this purpose, the Food Corporation of India has been set up. The Corporation is purchasing foodgrains from surplus States. The purpose of zonal restrictions is only to restrain the private traders from exploiting the situation of shortage and to help government procurement in surplus States. But unfortunately, the surplus States are not co-operating with the Centre in procurement. The States are moved by parochial considerations. Take, for example, Madhya Pradesh's 'no' to the Centre regarding Central procurement there. This is a serious handicap; without the active and full co-operation of the States, the Centre cannot fulfil this great responsibility of feeding the poor people, of procuring and distributing foodgrains through ration shops and fair price shops.

Can the Centre abolish the present zonal system and build up its own machinery? This problem is worrying the Central Government. They have set up an expert committee to examine possible alternatives to the present zonal system, the procurement system and distribution system. Government have an open mind in the matter and are prepared to do whatever is best for the common people of the country....

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up. Shri S. N. Das.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): The Resolution under discussion is so very general in character in the present circumstances of the country that it cannot be fully supported. The food situation in the country at present is very critical and there is a shortage of production. We have been importing very large quantities of foodgrains from other countries. Under such circumstances, to remove all barriers to the free movement of foodgrains and remove all controls on distribution, sale, price, procurement etc. will be detrimental to the interest of the consumers of foodgrains, especially the very vulnerable sections of society.

This question is being discussed throughout the country. It is being considered and debated here and outside. A very large section of people are against the zonal system. Here in this House, some hon. Members have supported it. But my opinion is that in this critical situation the country is faced with in respect of foodgrains availability when we have to depend very much on imports from abroad, it will not be in the interest of the country to abolish restrictions or barriers or the procurement policy of Government. This question requires very careful consideration. I am glad Government have appointed a committee to go into the matter. By a Gazette notification dated 15th March, the Committee has been appointed.

In this connection, I would say that in 1957 the Foodgrains Inquiry Committee was appointed by Government under the chairmanship of Shri Asoka Mehta. They went into the question thoroughly and suggested the establishment of a foodgrains price stabilisation organisation. Although that organisation was not set up, Government has brought into being the Foodgrains Corporation. The working of the Corporation has not been quite successful.

In this regard, I only suggest that because of the shortage of foodgrains in our country, some sort of control is necessary, some restrictions are essential. Which restrictions should be removed is to be considered very carefully by a special committee. Its report may be discussed by this House and we can come to our own conclusions. Here I would quote one recommendation of the Asoka Mehta

[Shri Shree Narayan Das]

Committee (p. 86, para 75 of their Report):

"We would like to emphasise here that until there is social control over the wholesale trade, we shall not be in a position to bring about stabilisation of foodgrain prices. Our policy should, therefore, be that of a progressive and planned socialisation of the wholesale trade in foodgrains."

Considering the way some of the very large number of traders have behaved in this country, I think if Government do not put restrictions or barriers at strategic places and areas, the country will be faced with a disaster, because there are very large areas in the country which are deficit in production. If zonal restrictions are removed, though it may provide some facilities, it may create difficulties also.

Therefore, this Resolution should not be accepted. As Government have already appointed a Committee to look into the matter, this Resolution should be withdrawn. Government should be given the opportunity of considering the report of that Committee. The House could also consider that report and could come to its conclusions with regard to this very important matter which is engaging the attention of the whole country.

With these words, I oppose this Resolution because it is too general to be accepted in present circumstances.

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, श्री तन सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उस का मैं विरोध करता हूं। उस की भावना और उस की स्प्रिट के साथ यद्यपि सारा देश है मगर जो उनके प्रस्ताव में यह शब्द हैं :—

"This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement and all zonal and other barriers to the free movement of foodgrains throughout the country be abolished immediately."

यह जो उन्होंने इम्मीजिएटेली ऐबौलिस्ड कहा है यह बहुत साइंटिफिक नहीं है। उन से हम लोग पूरे सहमत नहीं हैं। जैसा कि श्री श्रीनारायण दास जी ने बतलाया और हम लोगों ने भी देखा कि देश में खाद्यान्न की विषम स्थिति चल रही है और जिसके बारे में पोप साहब को कहना पड़ा और यह जो खाद्य संकट है यह केवल भारत में ही नहीं अपितु साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों में खाद्य स्थिति नाजुक हो रही है और यह सही है कि यू० एन० ओ० की जो फुड एग्रीकलचरल रिपोर्ट निकली है उसमें उन्होंने इन चीजों को बताया कि हालत यहां की इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। मगर यह बात सही है कि गांव गांव में लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि कुछ न कुछ अंश में फूड जोन्स का एबालिशन होना चाहिए। जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, सरकार को इसकी शुरुआत तो करनी चाहिए।

Let us have a beginning. At the last Jaipur Congress also, our Food Minister Shri P. G. Menon was present, and he saw the atmosphere in the Congress, and we came to the conclusion that a beginning should be made.

इसलिए हम लोगों को इस बारे में शुरुआत तो करनी ही चाहिए, बिगनिंग तो करनी चाहिए। कोर्स ग्रेन्ज के बारे में जो कानूनी अड़चन है, उस में कुछ न कुछ ढील देनी चाहिए, तभी हालत थोड़ी बहुत सुधरेगी। लेकिन यह काम हम सरकार पर छोड़ दें कि इस के लिए कौन सा आपरटून मोमेंट है, कब यह काम शुरू करना चाहिए।

अशोक मेहता कमेटी के निर्देश पर हम लोगों ने फूड कार्पोरेशन की स्थापना की।

पाई साहब उस के चेयरमैन थे, लेकिन पूरा सहयोग न मिलने के कारण उन को हटना पड़ा । यह स्थिति विचारणीय है ।

श्री रंगा और कुछ और माननीय सदस्यों ने किदवई साहब का हवाला दिया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है और पापुलेशन बहुत बढ़ गई है । यह ठीक है कि इरिगेशन के पोटेंशल को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए और वेस्टलैंड को खत्म कर के फ़र्टाइल और कल्टीवेबल लैंड बनाना चाहिए, लेकिन जब तक हम अपनी जनसंख्या को कर्ब नहीं करेंगे, तब तक हम इस समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर पायेंगे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी का सच्चा अर्थ यह होता है कि जनता की आवाज को सुना जाये और जनता में केवल पढ़े-लिखे अर्थ-शास्त्री ही नहीं होते हैं, बल्कि यहां जो लोग बैठे हैं, उन की बात को भी विचारना चाहिए ।

माननीय सदस्य, श्री तनसिंह, ने यह प्रस्ताव बहुत एक्स्ट्रीमिस्ट वे में रखा है । यदि वह इस को वर्तमान स्थिति को देखते हुए रखते, तो सारा सदन उन की आवना के पीछे होता ।

मैं चाहूंगा कि फूड मिनिस्टर साहब बराबर स्थिति को देखते रहें और वह इस बारे में कोई विगनिंग करें, लेकिन समय और स्थिति उन्हीं को निश्चित करनी है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : सभापति महोदय, जिन कांग्रेसी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, उन को मैं धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने इस बारे में लीपापोती की है, उन्होंने कांग्रेस टिकट लेने के लिए ऐसा किया है और मैं उन का विरोध करता हूं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने समय को देखते हुए यह प्रस्ताव पेश किया है कि ज़ोनबन्दी के सिस्टम को हटा दिया जाये । मैं इस प्रस्ताव का हृदय से और पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

मैं ने अपने यहां देखा है कि कोटा–चम्बल डैम पर काम करने के लिए मजदूर ट्रक पर बूंदी जाते हैं । मैं आप को एक दफ़ा का किस्सा बताना चाहता हूं कि जब वे लोग दोपहर को खाने के लिए रोटी बांध कर अपने साथ ले जा रहे थे, तो उन को चौकी पर रोक लिया गया और उन की रोटियां वहां ही रुकवा ली गई । यह कितने शर्म की बात है सरकार के लिए कि बेचारे मजदूर अपनी रोटी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं । यह बहुत बुरी बात है ।

कोटा और बूंदी की सीमा पर जो खेती होती है, उस में आधा खेत कोटा में है और आधा खेत बूंदी में है । जब किसान अपना माल बूंदी से कोटा को लाने लगे, तो बूंदी वालों ने उस अनाज को ज़ब्त कर लिया और उस को कोटा में नहीं आने दिया । यह कितने शर्म की बात है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अनाज नहीं लाने दिया जाता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की पाबन्दी से भ्रष्टाचार, चोरबाज़ारी, रिश्वतखोरी और डाकुओं को प्रोत्साहन मिलता है । शायद यह सरकार इस पाबन्दी को तब हटायेगी, जब इलैक्शन नज़दीक आ जायेगा । विशेषज्ञ समिति भी शायद इसी बात का इन्तज़ार कर रही है । लेकिन इस पाबन्दी की वजह से बेचारे किसान बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं । इस लिए इस स्थिति को देखते हुए सरकार को इसे जल्द से जल्द हटा देना चाहिए ।

हमारे यहां कलैक्टर ने आज्ञा दी कि गांवों से अनाज इकट्ठा किया जाये । हर एक तहसीलदार ने तीन-तीन हज़ार बोरियां इकट्ठी कर लीं । लेकिन सरकार के पास इन बोरियों को लाने के लिए एक पैसा भी

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

नहीं निकला । किसान अपने अनाज को न तो बाजार में बेच सकता है और न ही सरकार उस को ख़रीदती है । इसलिए चना सड़ रहा है और गेहूं जहां का तहां पड़ा हुआ है ।

राजस्थान में संकट-कालीन स्थिति है । ऐसी जगह जिलेबन्दी की गई है, जिस के कारण यह अवस्था है कि कोटा में अनाज पड़ा हुआ है, लेकिन वह जैसलमेर में नहीं जा सकता है । अगर जा सकता है, तो कलेक्टर या खाद्य मंत्री की परमिशन से और वे ऐसे आदमी को परमिशन या परमिट देते हैं, जो उन को वोटों या चन्दे से सहायता दे सकते हैं ।

"राजस्थान पत्रिका" में साफ़ लिखा हुआ है कि राजस्थान के टोंक जिले में नौ आदमी भूख से मरे । अगर यह जोन-बन्दी तोड़ दी जाये, तो सरकार कमी वाली जगहों में अनाज के ट्रक तुरन्त भेज सकती है, लेकिन अपनी इस नीति के कारण वह मजबूर है ।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि किसानों के पास जो अनाज है, उस को हम स्टाक कर लेंगे और अमरीका से जो भूसा आता है, वह किसानों को खिलाया जाये । प्रश्न यह है कि अमरीका के अनाज का स्टाक क्यों नहीं किया जाता है और क्यों न हमारे यहां जो अनाज पैदा होता है, वह लोगों को खिलाया जाये । लेकिन सरकार के पास न पैसा है और न स्टाक करने के लिए साधन हैं । इस के बावजूद वह आर्डर कर देती है कि हम पहले स्टाक करेंगे और उस के बाद पब्लिक को खिलायेंगे । यह कितने शर्म की बात है ।

सरकार अनाज को खुला करे, ताकि किसान को अपने उत्पादन का उचित दाम मिले । अगर एक व्यापारी पांच पैसे ज्यादा ले लेता है, तो उस को एरेस्ट किया जाता है और उसका लाइसेंस छीन लिया जाता है । कोटा, राजस्थान से 40 रुपये के हिसाब से लिया गया चना गुजरात में 89 रुपये के हिसाब से बेचा गया । मध्य प्रदेश में चना 48 रुपये में लिया गया और 105 रुपये में गुजरात में बेचा गया । मक्का राजस्थान से 38 रुपये में ख़रीदा गया और मद्रास में 78 रुपये में बेचा गया । इस तरह से यह सरकार ब्लैक-मार्केटिंग कर रही है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ब्लैक-मार्केटिंग नहीं करती है, लेकिन क्या यह ब्लैक-मार्केटिंग नहीं है ?

इस तरह जोनल सिस्टम बना कर सरकार खुद तो ब्लैक-मार्केटिंग करती है और बेचारे बिचौलिये को बदनाम करती है । वह उस को न एरेस्ट करती है और न उसके खिलाफ़ एक्शन लेती है और इस के बीच में किसान पिसा जा रहा है । वह अनाज को बाहर नहीं निकाल सकता है और सरकार उस को ख़रीदती नहीं है । आज किसानों को पैसे की जरूरत है । अनाज आने वाला है । शादियों का टाइम चल रहा है । इस प्रकार वे लोग बड़ी मुसीबत में हैं ।

सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण कानून बना कर लाखों सुनारों को बेकार कर दिया । लेकिन उस का नतीजा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि काम वैसे ही चल रहा है । उस कानून के द्वारा बेचारे सुनारों को पीसा गया । जोनबन्दी कर के किसानों को पीसा जा रहा है । इस से प्रकट होता है कि सरकार के सारे कानून रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल हैं । वह आंख मींच कर कानून बनाती है और फिर अपनी हठ पर अड़ी रहती है ।

माननीय मंत्री, श्री सुब्रह्मण्यम, ने कहा है कि हम अन्न के मामले में दस साल में आत्म-निर्भर हो जायेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां 125 लाख टन अनाज

की कमी है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, वह हर साल ज्यादा से ज्यादा पांच लाख टन बढ़ता है। इसलिए आत्म-निर्भर होने के लिए कम से कम पच्चीस साल तो चाहिए ही।

सरकारों को जोनल सिस्टम को तोड़कर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां भी अनाज की कमी हो, वहां अनाज भेजा जाये, किसानों को अपने उत्पादन का उचित दाम दिया जाये और भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी और रिश्वतखोरी को बन्द किया जाये। तभी इस देश का उद्धार हो सकता है और आत्म-निर्भरता प्राप्त हो सकती है।

Shri M. R. Krishna: I stand here to oppose this resolution. The reason is very obvious, because most of the programmes which the Government rightly introduced have become failures because the Government officials do not take these programmes very seriously and sincerely.

Shri K. Manoharan (Madras South): Including Ministers.

Shri M. R. Krishna: If procurement is entrusted to Government officers, one thing will definitely happen, and that is harassment of the small cultivators. The big cultivators, whether they produce wheat, rice or anything, will be able to get away, and they will conceal a lot of their produce in spite of the fact that the Government agencies know what amount of production has come from that particular field. Therefore, if this monopoly procurement is adopted, it will be really harmful to the small cultivators. Any Tahsildar will just send a note from his office asking a small cultivator to give a particular quantity of foodgrains, even when the grains produced may not be enough for his own consumption. Therefore I oppose this on the ground that Government officials will not be very sincere in implementing it, and secondly on the ground that it is going to harm the small cultivators.

We always try to have very big things without seriously thinking how to put them into action. Monopoly procurement may be all right but until and unless we tackle the more important things like land reforms, it will be impossible to have enough food production in the country. Added to this, PL 480 has really made the government officials and even the people who are dependent on agriculture to become a little slack. That was to help us to build buffer stocks but now it has become a permanent thing and so long as this continues the people and the government will not take things seriously. We have enough wheat and our main problem is rice. The rice producing areas are not being catered with fertilisers and other requirements. Without meeting these demands, I do not know how government is going to procure enough food. In some areas of Andhra, fertiliser is distributed at the rate of 1 Kg per acre to a cultivator. The main rice-growing areas are treated like this. If it is true, I cannot understand how sincere government is in enhancing food production. Land is available in some places, land reforms have been introduced. Government do not attach importance to some of their programmes. They just distribute some land to a fellow who cannot cultivate even one-tenths of what he has. Government thinks that the moment a man gets land he would produce grains. It would be just impossible from him to produce enough food crops from that land, unless credit facilities are provided. Government should allow credit facilities to small farmers and provide some common facilities. For instance, a small cultivator may not be in a position to own a pumping set or sprayers for pesticides and other kinds of things. These common services should be provided. People have started eating more because some of them are getting good salaries. In addition to that, we find from statistics, that even rats eat more. Six rats now eat one man's food. Formerly ten rats used to consume one man's food. I am told that there are 500 milion rats in the whole

[Shri M. R. Krishna]

world and many experts say that unless we control this kind of things it will be impossible for government to have enough food to provide for the people.

Mr. Chairman: You must conclude now. Five minutes are over. The hon. Minister .... (*Interruptions*). The demands for agriculture and other things are coming. You can say there these things.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): The House wants that the time should be extended. You can extend the time.

Mr. Chairman: If your party Member wants just five minutes, I have no objection. He can take five minutes.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : सभापति महोदय, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने, इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि देश में अन्न की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है, यह स्थिति आज सारे देश में फैल गई है । हिमालय से कन्याकुमारी तक सारे देश में, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में लाखों आदमी आज भूख से मर रहे हैं । मगर हमारा आरोप सरकार पर यह है कि सरकार की कोई अन्न नीति नहीं है । न तो यह सरकार पूरी तरह से जोन को हटाती है और न पूरी तरह से कन्ट्रोल करती है । इस की हर पालिसी चों-चों का मुरब्बा है, न इधर और न उधर । इसलिये आज जो जोनल रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, मैं नहीं समझता कि इस के हटाने के बाद उनकी हालत क्या होगी ? क्योंकि सरकार का कन्ट्रोल न व्यापारी पर है न सरकारी अधिकारियों पर है, किसी पर नहीं है, क्योंकि इसकी अन्न नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है ।

आज जोनल सिस्टम के अन्दर लोग खामख्वाह परेशान किये जाते हैं । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सस्ता गल्ला खरीद कर राज्य सरकार दूसरे राज्यों को महंगे दामों पर देती हैं, इस तरह से ये खुद इस में प्राफिट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ हमारे यहां के बहुत से लोगों को पकड़ कर इन्होंने जेलों में बन्द कर दिया है, इसलिये कि वे चोर-बाजार में धान बिहार से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे । जब कि वहां पर इनके पुलिस के लोग बैठे हैं और हजारों मन अनाज बिहार से उत्तर प्रदेश और दूसरी सीमाओं को पार करके जा रहा है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह जोनल व्यवस्था तब तक कामयाब नहीं हो सकती, जब तक सरकार पूरी तरह गल्ले का व्यापार अपने हाथ में न ले । आज न तो सरकार यह व्यापार पूरी तरह से अपने हाथ में लेती है और न ही इसे छोड़ती है । अभी-अभी आलू 6–7 रु० तक पहुंच गया और वहां सरकार ने यह एलान किया कि जिन जिलों में आलू ज्यादा होता है, वहां सरकार आलू खरीद करेगी, दो-तीन दिन से यह सब हो रहा है, आज किसान ने जो रुपया आलू और गन्ने की पैदावार में लगा रखा है, वह उसे नहीं मिल रहा है, पहले तो ये रोक लेते हैं और जब इस तरह से कम दाम में गल्ला महाजन के हाथ में चला जाता है, तो उनके लिये छूट कर देते हैं कि वे ले जा कर बेचें, इस तरह से उनको दुगना, तिगुना और चौगुना मुनाफ़ा होता है । इसलिये सरकार को चाहिये कि सही मायनों में गल्ले के व्यापार को अपने हाथ में ले ।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विरोधी इन बातों से फायदा उठाते हैं, कोई कहता है कि हिन्दुस्तान में भुखमरी नहीं है, बल्कि एशिया में भुखमरी है, मुझ को एक कहावत याद आती है, एक लड़का फेल हो गया, जब उस से पूछा गया तो कहता है कि मैं अकेले ही फेल नहीं हुआ, स्कूल में सारे लड़के फेल हो गये हैं । हमारे यहां करप्शन नहीं है, रूस में करप्शन है । रूस की बात

करते हैं, चीन की बात करते हैं, लेकिन यहां चीन की बात कौन पूछता है, आप इस मुल्क को खाना देने के लिये जिम्मेदार हैं। आप बताइये कि यहां पर भुखमरी क्यों है, इसलिये है कि आपकी कोई अन्न नीति नहीं है और आप ने देश को भूखा मारने का प्रोग्राम बनाया है, जान-बूझ कर यह प्रोग्राम आपका चल रहा है। बातें बड़ी-बड़ी आप बनाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि या तो जोनल सिस्टम हटाइये, नहीं तो आप के अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

मुझे मालूम है कि एक राज्य के कलेक्टर ने 25 हजार रुपया महाजनों से लिया, इसलिये कि दो दिन तक अनाज मत आने दो, हम को अनाज खूब महंगा करके बेच लेने दो। आपकी अन्न नीति लोगों को मजबूर करती है, हमारे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उससे आन्दोलन करने के लिये मजबूर हो गये हैं। वही चीज आज बंगाल में हो रही है, दूसरे राज्यों में हो रही है, इसलिये अपनी अन्न नीति को मूल रूप से परिवर्तित कीजिये ताकि लोगों को अन्न मिल सके और साथ ही साथ किसानों को ठीक दाम मिलने की गारन्टी हो।

Shri Govinda Menon: Sir, I am highly impressed by the genuine concern expressed by all sections of the House about the food problem in the country. The various difficulties which the people are facing on account of the scarcity of foodgrains, the corruption referred to by many hon. Members, the varying prices prevailing for foodgrains in different parts, the difficulties which are caused, as was said by some hon. Members, by the zonal system, the difficulties caused by procurement—all these were referred to by hon. Members here and I take it that all sections of the House are genuinely concerned over this matter. But let me also state that the Government is at least equally concerned over those difficulties. Let us now go into the real problem. Two aspects of the food problem have been referred to in this resolution—procurement and the zonal system, which has been introduced according to me to enable proper procurement. But that is the least important aspect. In a situation of scarcity when it is admitted on all hands that we have not got enough foodgrains to go round, government have a supreme duty of distribution. That is the most important aspect of the problem.

Take some very deficit regions in the country today. The foodgrains distributed per adult per day comes to 9 to 11 ounces which, it is agreed on all hands, is not really sufficient. But that alone is available. So, the government has taken upon itself, rightly so as hon. Members would agree, the responsibility of distribution with two objectives, namely, there should be equal distribution to the extent possible and there should be a system under which prices do not go up very much. It is no good if the poor people who have no foodgrains of their own to live upon are constrained to pay heavy prices. Everyone knows that in a situation in which supply is much less than the demand, if things are left alone, prices would go up. So, the object of food policy—whether it has been properly achieved or not is a different matter—is to distribute foodgrains particularly in the deficit areas equally and at moderate prices.

Shri Ranga: To the rich and middle classes also, which means you are subsidising rich people's food. That is what it comes to.

Shri Govinda Menon: We are not subsidising. As I said, it is the government's duty to distribute equally and this responsibility cannot be given up. If that is conceded, Government have to procure grain. Unless government have stock in their possession, how can it take up the responsibility of distribution? This resolution says that monopoly procurement should be abolished and the trade

[Shri Govinda Menon]

should be allowed to compete with the Food Corporation in the matter of procurement throughout the country. That, I believe, is the meaning of this resolution. It is a very plausible suggestion; it is a counsel of perfection if the object of food policy is to procure only. But if the object is also to distribute, we come to a dead end. The Food Corporation, as the agency of the administration, procures in order to distribute. Merchants procure in order to sell at a profit. When the supply is much less than the demand and there is deficiency in the country, even if all the available surplus goes into the hands of the government, it will not be sufficient for proper distribution. So, if a good portion goes into the hands of the trade also, there will be difficulties.

Shri Ranga: What about imports?

Shri Govinda Menon: Even with imports, this is the position.

The resolution says that monopoly procurement should go. But is there monopoly procurement except in two or three States? Monopoly procurement exists today only in West Bengal and Maharashtra. (*Interruption*). Also, to some extent, in Kerala where there is a levy which approaches monopoly procurement.

Shri Bade: In Madhya Pradesh also there is monopoly procurement.

Shri Govinda Menon: The hon. Member is confusing probably between procurement and monopoly procurement. In a system of monopoly procurement the trade will not be allowed to operate. What is done in West Bengal and what is done in Maharashtra is ..... (*Interruption*). The method of compulsory monopoly procurement has been adopted only by these States, and there the system is that all private trade in specified foodgrains above a given specified quantity which varies from 15 kilograms to 75 kilograms has been taken....

Shri Bade: In Madhya Pradesh nobody can purchase wheat or jowar from any agriculturist.

Shri Ranga: Nobody can export from one State to another.

Mr. Chairman: Let the hon. Minister have his say.

Shri Govinda Menon: There are two or three States where there is anything like monopoly procurement. Be it noted, these are deficit States where the State Governments thought it fit to have a system of procurement. In the absence of procurement in those highly deficit areas what would happen is that the poor people will get nothing and the rich people will get the foodgrains because prices will go up. In a situation like that Government have intervened and have adopted a system of procurement in order to enable Government to distribute. My submission is that the object of the food administration is to see that there is proper food distribution.

Shri Ranga: It is not there and you can never achieve it.

Shri Govinda Menon: The object is to see that there is proper distribution particularly in the deficit areas. It is no use interrupting me like this. I say that is the object. Wherever rationing has been introduced it has been possible for the Government to distribute a certain minimum quantity to the people. That alone is possible under the circumstances.

Now, if this resolution is adopted, if procurement is given the go-by, Government will not be able to do even that and no distribution will become possible. I do not think there is any section of the House which would advocate a situation in which there will be no distribution of foodgrains to the people particularly in the deficit areas at a certain equal quantity and at certain prices which are moderate. The result of taking away the machinery of distribution

would be to cause difficulties to the people who have no money, who are poor people.

Shri Ranga: There were fair price shops before this system has been brought in, these zonal restrictions and all these check posts have been brought in. They certainly served the people.

Shri Govinda Menon: I am now speaking of procurement, I will come to the zonal system later; let my venerable friend be patient to hear me.

There are two aspects in this resolution: one an attack on procurement and another on the zonal system. The two are different. Procurement has to be resorted to in a situation which obtains in India today in order to enable the Government to have a proper system of distribution. Several systems of procurement may be resorted to. Certain States have adopted a certain system and certain other States have adopted a certain other system. For example, there is a system in Andhra Pradesh where there is a levy on the mills. There is a certain other system in certain other States, but the object of all this procurement systems is to see that the administration has in its possession foodgrains which with the imported grains will be utilised with the object of equitable distribution at proper prices to the people. That aspect of the problem has been forgotten by some hon. Members. I do not say that they are against that. But it has not been emphasized. If it is emphasized, I am sure every section of the House will agree with me that some system of procurement is necessary. But that system can certainly not be the system advocated by Professor Ranga, because that will be good only so far as procurement is concerned. But if the objective of procurement is controlled distribution, then there is no use merchants being allowed to procure, because they procure in order to stock and sell and sell for profit.

17 hrs.

Shri Ranga referred to a situation in which there will be fair price shops. But that was the system when the scarcity was not so pronounced as it is today. Two or three years back, when our difficulties were not so acute as it has been during the last 12 to 15 months, that system worked but that system may not work now when there is scarcity of this magnitude. Therefore, I have to say that Government cannot accept this sweeping demand that procurement should be given up.

Compulsory procurement is not extant in all parts of the country. It is extant only in certain parts of India and, depending upon the conditions prevailing in those areas the State Governments there—please do not forget that this is the result of directions issued by the Food Ministry—the State Governments decide upon the *modus operandi* which they would have in order to have adequate stocks of foodgrains with them. Certain Governments have a system of levy; certain Governments have a system of monopoly procurement; certain Governments have some other system. But procurement must be there.

There has been an attack from many sections of the House against the zonal system. The zonal system is not an end in itself. It was adopted because it was thought that in that system alone, as it obtains today, would it be possible for the administration or the Food Corporation to get the maixmum quantity by procurement. Now the objection against the zonal system, as I understood it, is not that there should be no zones but what should be the extent of the zones, whether all India should be one zone, whether each State should be a zone or whether the 50 and odd surplus districts should be each a separate zone. That is the controversy.

Because of the demand from all sections of the House that there should

[Shri Govinda Menon]

be a change in the zonal system, Government have appointed a Committee to go into the question. This fact was announced in this House and in the other House. It was done a few days back. Some of the most prominent and eminent economists of the country are serving as members of this Committee. The Committee will certainly look into all aspects of the problem and it will be open to the House to give its view after the report of the Committee has come. To demand that the Government should, here and now, make a declaration that the zonal system would be abolished, especially after the Government have apponited a Committee to go into the very same matter . . .

Shri Ranga: You did it to delay things.

Shri Govinda Menon: ....to look into the *pros and cons* of the matter, is too large a demand. I think it is uncharitable on the part of Professor Ranga to say that the Committee was appointed to delay matters. After all, what is it that the Government achieve by maintaining a system which is bad? Certainly, Government have no vested interest in the zonal system. I do not think anybody would say that.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): The State Governments have got it.

Shri Govinda Menon: I am speaking of the Union Government. We have no vested interest in the zonal system and if, as has been suggested, the State Governments have a vested interest, that is a matter which is being looked into, gone into, by the Committee.

That being the position, let me just give the salient points which I wanted to make before the House. Firstly, in a situation of scarcity such as we are having today, it is the duty of Government under the Constitution and otherwise to see that there is an equitable system of distribution so that the poor people will get their share and they will not have to pay very high prices. For that purpose procurement is necessary. Procurement cannot be given up. You cannot have a system of free trade in foodgrains which is most essential for the people when there is scarcity in the country.

Shri Ranga: Not for animals.

Shri Govinda Menon: What is the use of making interruptions of the type which Professor Ranga, a very senior Member, made when I was saying, "foodgrains which are most important for human beings"? I never thougnt that a man of the maturity of Professor Ranga would interject to say, "And not for animals". That is introducing a certain amount of levity in this debate which the subject matter of the debate does not warrant . . . (*Interruption*).

Mr. Chairman: There should be no running commentary.

Shri Ranga: I sympathise with the poor man. What can I do?

Shri Govinda Menon: I do not sympathise with Professor Ranga.

The position is that in a commodity like foodgrains, which is in short supply, an absolutely free trade and a *laissez faire* arrangement would create conditions in which the poor people will suffer extremely and there will be starvation deaths.

Shri Ranga: Did I refer to a *laissez faire* policy? Have I not made it very clear to you that I wanted the Government to maintain minimum prices?

Shri Govinda Menon: That is why I say that Professor Ranga had a look at a truncated problem, namely, procurement only. If the object is to see that the agriculturists get a fair price and for that purpose a scheme of procurement should be devised, then

Professor Ranga has given us a counsel of perfection, but procurement is for another end. Procurement is not an end in itself; procurement is intended to enable the administration to have equal distribution at prices which are moderate. If that is the object, and when I tried to make that point, why should Professor Ranga just interrupt?

So, what I submit is that procurement is necessary and therefore a sweeping resoltuion like this demanding that monopoly procurement should be given up, is something which should not be accepted by the House.

Regarding the zonal system, there have been comments in this House and there have been opinions expressed in this House and outside, and the Government have responded. Government did not want to take the responsibility to do something which may lead us to trouble because Government have difficulties. Therefore, Government invited some of the most eminent economists in the country to work in a committee to give us a report. That is where the matter stands. That being so, having accepted the sincere concern of all sections of the House in the matter raised in this debate, I should think Government cannot accept this Resolution and Government have to oppose it.

श्री तन सिंह : सभापति महोदय, सरकार के लिए विरोधी पक्ष से आने वाले प्रस्ताव को न मानना एक स्वाभाविक बात है और अगर यह प्रस्ताव मेरा वह मान लेते तो यह कांग्रेसी सरकार ही नहीं रहती । बहुत से सदस्यों ने बताया कि जहां तक प्रस्ताव की भावना और उद्देश्य का सवाल है उससे तो वे सहमत हैं और ऐसा कहने वालों में कांग्रेसी सदस्य भी थे लेकिन यह कि इस प्रस्ताव को जल्दी में स्वीकार कर लेना उचित न होगा और पता नहीं इसको स्वीकार करने का क्या नतीजा निकले, इसलिए उन का सुझाव है कि इस विषय पर कोई ऐक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाय और उससे रिपोर्ट ली जाय । अब जहां तक ऐक्सपर्ट कमेटी बैठाने का सुझाव है पता नहीं कब तक वह अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और कब तक सरकार उस बारे में अपना अंतिम निश्चय करेगी ? पिछला अनुभव हम लोगों का इन ऐक्सपर्ट्स कमेटियों के बारे में अच्छा नहीं रहा है । हाइड्रोजनेटेड वेजीटेबुल घी के बारे में एक कमेटी बैठाई गई थी और उसे बैठाये भी कोई 6 या 7 वर्ष से अधिक हो चुके हैं लेकिन वह अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दे सकी है । मेरी तो समझ में अगर किसी चीज को टालना हो और लटकाये रखना हो तो बस एक कमेटी बैठाने की बात कह दो । हमारी सरकार ने भी इस कमेटी की नियुक्ति क्यों की है ? ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा कि जनमत कुछ भीतर और बाहर इस प्रकार का बन गया जिसके कि कारण विवश होकर उनको अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ गयी । यदि यह आवश्यकता महसूस नहीं होती और भारत का जनमत वैसा न चाहता तो इस ऐक्सपर्ट कमेटी के बैठाने की आवश्यकता नहीं होती ।

श्रीमन्, अभी बड़े प्रयत्न और परिश्रम से माननीय मंत्री ने जो कारण बतलाये हैं, मोनोपली प्रोक्योरमैंट खत्म करने के विरुद्ध, और वैसे तो बहुत से सदस्यों ने भी जो बातें कहीं वह विषय पर न जाकर उन्होंने विषयान्तर होकर अपनी वह सब बातें कही हैं । मेरी तो समझ में उनकी बातें नहीं आईं और मेरे गले के नीचे यह बात उतरती नहीं है कि आखिर मोनोपली प्रोक्योरमैंट का इससे क्या अभिप्राय है ? माननीय मंत्री ने बतलाया कि यह जो सरकार का मोनोपली प्रोक्योरमैंट है यह ओनरस इयूटी है और यह उनका प्रोक्योरमैंट फौर डिस्ट्रिब्यूशन है जबकि इसके विपरीत ट्रेडर्स का प्रोक्योरमैंट फौर सेल होता है । क्या माननीय मंत्री स्पष्टता से और बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकते

[श्री तन सिंह]

हैं कि उन्होंने जो डिस्ट्रिब्यूशन किया है वह सेल के ढंग से नहीं हुआ ? अब 38 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा और उसके द्वारा वह 78 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा गया तो यह डिस्ट्रिब्यूशन है या सेल है ? जिस भाव से खरीदते है उस के ऊपर केवल उपयुक्त पैसा लगा कर अगर डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं तब तो मैं समझता हूं कि वह गवर्नमैंट वाकई डिस्ट्रिब्यूशन करती है वरना नहीं । गवर्नमैंट कहती तो है कि हमारा प्रोक्योरमैंट डिस्ट्रिब्यूशन के लिए है लेकिन वास्तव में इसमें और ट्रेडर्स में कोई फर्क नहीं है क्योंकि मौका आने पर दोनों ही नफ़ा कमाने की चेष्टा करते हैं, जितना नफ़ा ट्रेडर्स कमाने की कोशिश करते हैं उतना ही नफ़ा सरकार भी कमाना चाहती है ।

श्रीमन्, सरकार जो एक यह बात मान कर चलती है कि अलावा उस के और देश में कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं और उस ने जो यह समझ रखा है कि जितने भी व्यापारी हैं वह सब बदमाशी करते है और जो व्यापारी वर्ग है वह ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकता यह उसकी गलती है । यह जो एकाधिकार का सिद्धान्त है वह जनतंत्र के सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत है, राजनीतिक दृष्टि से भी एकाधिकार का सिद्धान्त गलत है और राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी यह गलत है और जब ऐसी बात हो तो फिर यह एकाधिकार अर्थ तंत्र में कैसे ठीक हो गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ? एकाधिकार का मूल अभिप्राय शोषण होता है अब वह शोषण चाहे एक व्यापारी करता हो या चाहे फिर सरकार ही उसे करती हो और चाहे कोआपरेटिव सोसाइटीज करती हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । यदि एक व्यापारी शोषण करे और एक सरकार शोषण करे तो शोषित तो मानव मात्र ही होता है । मैं निवेदन करूंगा कि प्रोक्योरमैंट के कारण जो स्थिति पैदा हुई वह या तो सदस्य महोदयों को या विशेष कर मंत्री महोदय को पता नहीं है या फिर जानबूझ कर हठधर्मी कर रहे हैं । लेकिन मुझे वह अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूं । 200 क्विंटल बाजरे के प्रोक्योरमैंट के लिए मांग की गई थी जबकि वहां पर इतना पैदा ही नहीं हुआ था । कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्रोक्योरमैंट का पैट्रन बन गया है वह सारे देश का एक ही है बाकी कहीं कितना ऐक्चुएली पैदा हुआ है या नहीं हुआ है इस बात पर विचार नहीं किया जाता है और वही एक पैट्रन फिक्स कर दिया जाता है और उस के कारण कितना भ्रष्टाचार होता है यह हम से छिपा नहीं है । कितना उस के कारण पटवारी को पैसा दिया गया और कितना बीच के अफसरों को दिया गया और तब आखिरकार सरकार ने निश्चय कर लिया कि राजस्थान में यह नहीं होगा ।

अब मैं आप से निवेदन करूंगा कि यदि सरकार यह कहती है कि आजकल हमारी खाद्यान्न की स्थिति बड़ी विषम हो गयी है और हम इस मोनोपली प्रोक्योरमैंट को नहीं हटा सकते तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब पी० एल० 480 के मुताबिक 10 मिलियन टन अन्न हम ले रहे हैं अमरीका से और हमारे यहां का उत्पादन लगभग 9 से 12 मिलियन टन है, जब हम साल भर में जितना उत्पादन नहीं करते उतना अन्न हम बाहर विदेशों से मंगा रहे हैं और फिर भी हमारी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम अपने हाथ में इस प्रोक्योरमैंट मोनोपली को रखना चाहते हैं जोनल सिस्टम को रखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि परिस्थिति वास्तव में ऐसी नहीं है बल्कि वह दिखाने के लिए बनाई जाती है और सरकार जैसे वह सदा बतला देती है कि एक कमेटी बना दी गई है वह इस पर गहराई से सोचेगी तो मेरा ऐसा खयाल है कि जो मैं चाह रहा हूं

वह तब करेगी और यह मोनोपली और बैरियर्स हटेंगे लेकिन वह तब हटेंगे जब चुनाव बहुत नजदीक आ जायेंगे और तब सरकार वोटर्स से यह कहने की स्थिति में होगी कि हम ने आप के लिए यह फ़ायदा कर दिया ।

अब मैं संक्षेप में जोनल सिस्टम के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यह बात निर्विवाद सत्य है और प्रायः हमारे इस सदन के करीब करीब सभी सदस्यों ने और कांग्रेस के कई अत्यन्त प्रभावशाली सदस्यों ने भी इस विषय पर अपना मत प्रकट किया है कि जोनल सिस्टम मानव द्वारा लगाई गई एक अड़चन है । उस के कारण भाव बढ़े हैं और उसके कारण यह कठिनाइयां पैदा हुई हैं लेकिन सरकार अभी तक इतना समय हो गया है कोई निश्चय क्यों नहीं कर रही है ? उस के लिए सरकार कमेटी क्यों बैठाने को सोच रही है ? मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी अड़चन है । अड़चन सिर्फ एक ही है और वह यह कि उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर है । उसने गलत नीतियों का निर्धारण किया और उसे कहीं अचानक कोई एक व्यक्ति कह दे, विरोधी पक्ष का कह दे या अपनी तरफ़ का ही व्यक्ति कह दे कि वह गलती पर है तो वह कैसे उसे स्वीकार कर ले क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा जाती रहती है । केवल प्रतिष्ठा के कारण ही सरकार इस जोनल सिस्टम को नहीं हटा रही है वरना कोई तर्कसंगत बात अगर उसके पक्ष में वह बतलाते तो मैं उसे समझ भी सकता था और मानने को भी तैयार हो सकता था लेकिन ऐसी कोई तर्कसंगत दलील उन्होंने इसे बनाये रखने के लिए नहीं प्रस्तुत की है ।

अब जहां तक प्रतिष्ठा का सवाल है तो यह प्रतिष्ठा का सवाल चुनाव जीतने के लिए एक बहुत उपयुक्त नारेबाजी हो सकता है लेकिन देश में अन्न वितरण के लिए और देश के गरीब लोगों के लिए यह लाभप्रद बात नहीं होगी । श्रीमन्, यदि यही स्थिति बनी रही तो किसान अन्न उत्पादन करने के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं होगा जितना कि वह दूसरी चीजों के उत्पादन करने में होगा । यदि बाजरे का उत्पादन करने में 44 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है तो वह ऐसी ही वस्तु का उत्पादन करने का निश्चय करेगा जो मोनोपली प्रोक्योरमैंट में न आने वाली हो और जिस चीज के लिए कि जोनल रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा और जिसकी कि क़ीमत उसको 44 रुपये से ज्यादा मिलेगी ।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यदि सरकार ने इस प्रकार से वितरण का काम अपने हाथ में न लिया होता तो आलू के दाम यू० पी० में बहुत अधिक गिर गये होते । मैं नहीं जानता कि उसका और इस प्रस्ताव से क्या सम्बन्ध है ? अब यदि किसी जगह भाव गिर गये हैं तो मैं भी यह समझता हूं कि किसान का वास्तविक हित इस बात में है कि उसे उसकी उपज के उचित मूल्य मिलें बाक़ी मोनोपली प्रोक्योरमैंट से इसका क्या सम्बन्ध आता है ? मोनोपली प्रोक्योरमैंट में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि उस वस्तु की क़ीमत क्या हो ? उस के लिए एक ऐडहौक कमेटी बना जरूर दी गई है बाक़ी जो उसके द्वारा प्रोक्योरमैंट के भाव निश्चित किये गये हैं उन भावों में और वास्तविक बाजार के भावों में कोई संतुलन नहीं है । अब वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए प्रोक्योरमैंट प्राइस फिक्स की जाय और प्रोक्योरमैंट सरकार करे अथवा फूड कारपोरेशन वह भी इस तरह से कर सकती है, प्रोक्योरमैंट कर सकती है, खरीद सकती है और दूसरे लोग भी खरीद सकते हैं और ऐसा होने से किसानों को फायदा होगा इसमें कोई शक नहीं है । लेकिन यदि इस प्रकार से वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए यह काम नहीं किया जायगा तो इसका जो एक मनोवैज्ञानिक असर हमारे उत्पादन पर पड़ेगा उसका गम्भीर परिणाम भी हो सकता है ।

Mr. Chairman: I will now put the Resolution to the vote of the House.

The question is . . .

Shri Shree Narayan Das: On a point of order. The amendment moved by Shri Madhu Limaye has not been disposed of.

Mr. Chairman: It has not been moved at all.

The question is:

"This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement and all zonal and other barriers to the free movement of foodgrains throughout the country be abolished immediately."

The Lok Sabha divided:

Division No. 9] AYES [17.24 hrs.

Bade, Shri	Himmatsinhgi, Shri	Reddy, Shri Narasimha
Bheel, Shri P. H.	Ranga, Shri	Tan Singh, Shri

NOES

Alagesan, Shri	Malaichami, Shri	Roy, Shri Bishwanath
Barua, Shri R.	Malaviya, Shri K. D.	Saraf, Shri Sham Lal
Brajeshwar Prasad, Shri	Mandal, Dr. P.	Sharma, Shri A. P.
Chaudhry, Shri Chandramani Lal	Mehrotra, Shri Braj Bihari	Sheo Narain, Shri
Deshmukh, Shrimati Vimalabai	Menon, Shri Govinda	Shree Narayan Das, Shri
Dubey, Shri R. G.	Mohanty, Shri Gokulananda	Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Gupta, Shri Shiv Charan	Mukane, Shri	Tantia, Shri Rameshwar
Hem Raj, Shri	Musafir, Shri G.S.	Tiwary, Shri D. N.
Imbichibava, Shri	Muthiah, Shri	Tiwary, Shri R. S.
Iqbal Singh, Shri	Rane, Shri	Uikey, Shri
Karuthiruman Shri	Rao, Shri Jaganatha	Varma, Shri Ravindra
Laskar, Shri N.R.	Reddy, Shrimati Yashoda	Wadiwa, Shri

श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी (महुआ): चेयरमैन साहब, मेरी मशीन ने वर्क नहीं किया है। मेरा वोट "नोज" में काउंट किया जाये।

Mr. Chairman: It will be noted.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): The result shows that we are less than 50.

An hon. Member: There should be at least quorum.

Mr. Chairman: The vote on this will be taken again on the next day.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The bell may be rung again.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, as there is no quorum.

17.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, March 28, 1966/Chaitra 7, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS II—3007(Ai) LS 15-6-66—970